प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

09.09.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

मुख्य समाचार

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण– त्वरित वित्तीय सहायता के तौर पर 15 सौ करोड़ रूपए देने की घोषणा।
- प्रधानमंत्री द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने व वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेताओं ने जताया आभार।
- मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री से विशेष राहत पैकेज और वन संरक्षण अधिनियम में छूट प्रदान करने का किया आग्रह।
- सोलन ज़िला के परवाणु शहर को प्रतिष्ठित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देशभर में मिला दूसरा स्थान।

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश का दौरा कर बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ से प्रभावित इलाकों चम्बा, भरमौर, कांगड़ा और अन्य क्षेत्रों का अवलोकन किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए फौरी राहत के तौर पर 15 सौ करोड़ रुपये की त्वरित वित्तीय सहायता की घोषणा की। बाद में प्रधानमंत्री ने कांगड़ा हवाई अड्डे पर एक समीक्षा बैठक कर राहत व पुनर्वास कार्यों की प्रगति और आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य आपदा राहत कोष एस.डी.आर.एफ. की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत राहत का प्रावधान और राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार और प्रभावित पशुपालकों के लिए मिनी किट्स भी वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त मकानों की जियो–टैगिंग की जाएगी जिससे नुकसान का सही आकलन और प्रभावित परिवारों तक त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके। इसी तरह क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की भी जियो–टैगिंग की जाएगी ताकि समय पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत आवश्यक मदद मिल सके। और ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता.....

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आज का हिमाचल प्रदेश दौरा आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत और भरोसा लेकर आया है। ज़मीनी स्तर पर पहुँचकर प्रभावित परिवारों से मुलाक़ात और राहतकर्मियों का उत्साह बढ़ाकर प्रधानमंत्री ने एक मज़बूत एकजुटता का संदेश दिया। नुकसान का आकलन करने के बाद प्रधानमंत्री ने राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए प्रदेश को पन्द्रह सौ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। प्रभावित परिवारों से मुलाक़ात के दौरान श्री मोदी ने संवेदनाएँ व्यक्त कीं और आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार घरों, स्कूलों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढाँचे पुनर्स्थापित करने में हर संभव मदद देगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए दो–दो लाख रुपये और घायलों के लिए पचास हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आपदा मित्र स्वयंसेवकों के त्वरित राहत व बचाव कार्यों में अथक प्रयासों की विशेष तौर पर सराहना की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि इस संकट की घड़ी में वे अकेले नहीं हैं और केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर तब तक काम करती रहेगी, जब तक हिमाचल पूरी तरह से इस आपदा से उबर नहीं जाता। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश में बाढ़ और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 15 सौ करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि एस.डी.आर.एफ. और पीएम किसान निधि की दूसरी किश्त के अग्रिम वितरण का निर्णय सराहनीय है और इन उपायों से प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी।

जे.पी. नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल में बाढ़ व अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और 15 सौ करोड़ की वित्तीय सहायता देने के लिए उनका धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि और एस.डी.आर.एफ. की दूसरी किश्त का अग्रिम भुगतान होने और आपदा में क्षतिग्रस्त घरों का पीएम आवास योजना के तहत पुनर्निर्माण व मुरम्मत सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार जैसे महत्वपूर्ण कदम देवभूमि की जनता को संबल प्रदान करेंगे।

जयराम ठाकुर

इस बीच, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत के लिए आर्थिक सहायता देने और प्रदेश में भारी बारिश व भूस्खलन से हुए नुकसान का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है। कांगड़ा में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल का दौरा कर आपदा प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाने के साथ उन्हें हिम्मत भी दे गए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने प्रदेश में प्रभावितों को मकान बनाने के लिए ज़मीन देने को लेकर फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट में संशोधन का प्रधानमंत्री से आग्रह किया जिस पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार का भरोसा दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गई सहायता राशि को प्रभावी लोगों के बजाय प्रभावितों के पुनर्वास और उन्हें राहत प्रदान करने के कार्यों पर खर्च करेगी।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री के साथ हुई समीक्षा बैठक में हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष हिमाचल से जुड़े विभिन्न मामलों को उठाया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से वन संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य को छूट प्रदान करने का आग्रह किया ताकि प्रभावित परिवारों को वन भूमि पर बसाया जा सके। उन्होंने केन्द्र से 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति देने का भी अनुरोध किया ताकि प्रभावितों को राहत प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने आपदा से क्षतिग्रस्त सरकार की परियोजनाओं के लिए अपर्याप्त सहायता को रेखांकित करते हुए वर्तमान मापदण्डों में संशोधन पर बल दिया। उन्होंने राज्य की विकासात्मक परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग भी की।

मुख्यमंत्री ने जलविद्युत से मुफ्त रॉयल्टी, 40 वर्षों के बाद केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व वाली बिजली परियोजनाओं को हिमाचल को हस्तांतरित करने की मांग को भी दोहराया। सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और प्रदेश के लिए बहुमूल्य समय देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश के लिए फौरी सहायता के रूप में 15 सौ करोड़ रुपये की घोषणा स्वागत योग्य है।

प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वाशन दिया है कि मैं आपको 1500 करोड रुपए की सहायता फौरी राहत के तौर पर दूंगा अब 1500 करोड़ क्या स्पेशल रिलीज पैकेज के तौर पर आता है या स्कीम बेस्ड आता है यह देखने की बात है और निश्चित रूप से हमारा यह मानना है कि जब उन्होंने पूरे हालात को देखा वो हिमाचल प्रदेश में पहले भी यहां भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज के रूप में कार्य

कर चुके हों। हिमाचल के परिपेक्ष में हमने उनको अपनी प्रेजेंटेशन दिए ।अब सहायता का जो घोषणा करके गई है अब उसका इंतजार है कि वह जल्दी लागू हो और सहायता से पहले हमें जो वन अधिकार नियमों में परिवर्तन करना है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि नुकसान बहुत हुआ है। अभी मैं तत्काल रूप में करता हूं अब देखते हैं आगे कि वह कितना पैसा और देने की घोषणा करते हैं।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार वन भूमि से जुड़े नियमों में आवश्यक संशोधन, सड़क निर्माण में टनलिंग और अन्य मुद्दों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र निर्णय लेगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, यादवेन्द्र गोमा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज और कंगना रनौत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पुरस्कार

सोलन ज़िला के परवाणु शहर ने प्रतिष्ठित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव और पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आज प्रदेश को इस अवॉर्ड से सम्मानित किया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल को 25 लाख रूपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

मौसम

प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ रहने से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य युद्धस्तर पर चलाए गए। कुल्लू जिला के निरमंड उपमंडल के घाटू पंचायत के शर्मानी में बीती रात हुए भूस्खलन की घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है जबकि तीन अन्य घायल है। एन.डी.आर.एफ. की टीम ने सभी शवों को निकाल लिया है। इस बीच, कुल्लू ज़िला प्रशासन ने बंजार व मनाली उपमंडल में कल 10 और 11 सितंबर को सभी निजी व् सरकारी शिक्षण संस्थानों सहित आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने की सम्भावना जताई है।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण– त्वरित वित्तीय सहायता के तौर पर 15 सौ करोड़ रूपए देने की घोषणा।
- प्रधानमंत्री द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने व वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेताओं ने जताया आभार।
- मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री से विशेष राहत पैकेज और वन संरक्षण अधिनियम में छूट प्रदान करने का किया आग्रह।
- सोलन ज़िला के परवाणु शहर को प्रतिष्ठित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देशभर में मिला दूसरा स्थान।